

वर्ष 2025-26 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाजारों के विभिन्न हिस्सों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रयास जारी रखे। इसके लिए उसने भागीदारी को बढ़ाया, पहुँच को सुगम बनाया और विनियमों को विकासमान कारोबारी प्रथाओं के साथ युक्तिसंगत बनाया। इसका उद्देश्य अनुपालन का बोझ कम करना और कारोबार को अधिक सुगम बनाने के साथ-साथ परिचालनगत क्षमता बढ़ाना है।

V.1 रिज़र्व बैंक ने विनियमों को सुव्यवस्थित कर और नवोन्मेष को बढ़ावा देकर वित्तीय बाजारों को और अधिक विकसित करने और गहन बनाने के प्रयास जारी रखे। वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) ने वित्तीय बाजार अवसंरचना को आधुनिक बनाने की कोशिशें जारी रखीं। वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) ने चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क में संशोधन किया। विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) ने अनुपालन का बोझ कम करने के लिए कई कदम उठाए और प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों को सीमा-पार व्यापार लेनदेन के लिए चयनित क्षेत्राधिकारों में अनिवासियों को भारतीय रुपया (आईएनआर) में ऋण देने की अनुमति दी।

V.2 उक्त पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को चार खंडों में बाँटा गया है। खंड 2 में वित्तीय बाजारों की गतिविधि और विनियम शामिल हैं। खंड 3 में रिज़र्व बैंक के बाजार परिचालनों पर चर्चा की गई है। खंड 4 में, बाह्य व्यापार और भुगतान, और उदारीकरण और बाह्य वित्तीय प्रवाह के विकास से जुड़े प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खंड 5 में निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.3 एफएमआरडी को, मुद्रा, सरकारी प्रतिभूति, ब्याज दर व्युत्पन्नी, विदेशी मुद्रा और क्रेडिट व्युत्पन्नी बाजार के विकास, विनियमन और चौकसी की ज़िम्मेदारी दी गई है।

2025-26 के लिए एजेंडा

V.4 विभाग ने 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी बाजार में अधिक पारदर्शिता लाने के प्रयास जारी रखते हुए, ओटीसी व्युत्पन्नी लेनदेन के लिए विशिष्ट लेनदेन पहचानकर्ता (यूटीआई) की आवश्यकताओं को वैश्विक प्रथाओं के अनुसार भारत में लागू किया जाएगा (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ V.5]; और
- विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स)-रिटेल को भारत कनेक्ट (पहले भारत बिल भुगतान प्रणाली) से जोड़ा जाएगा ताकि विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स)-रिटेल प्लेटफॉर्म की पहुँच बढ़ाई जा सके और उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। इसकी शुरुआत एक प्रायोगिक परियोजना से होगी जिसमें व्यक्तियों और एकल स्वत्वधारी को रुपये के बदले यूएस डॉलर खरीदने की सुविधा होगी (पैराग्राफ V.6)।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.5 ओटीसी व्युत्पन्नी लेनदेन के लिए यूटीआई को अधिदेशी बनाने वाले निदेश 18 फरवरी 2026 को जारी किए गए थे। इसके अलावा, विनियामकीय निदेशों की पहुँच को बेहतर बनाने और कारोबार सुगमता के लिए, विधिक इकाई पहचानकर्ता और यूटीआई संबंधी निदेशों को 'वित्तीय बाजार

में विशिष्ट पहचानकर्ता पर एकल मास्टर निदेश में समेकित किया गया था, जो 27 मार्च 2026 को जारी किया गया।

V.6 फॉरेक्स-रिटेल को 7 अक्टूबर 2025 को भारत कनेक्ट से जोड़ा गया। पहले चरण में, व्यक्तियों को यूएस डॉलर खरीदने की सुविधा दी गई है।

प्रमुख पहल

V.7 रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी (आईआरडी) संबंधी वर्तमान विनियामकीय फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई और 8 दिसंबर 2025 को इसे फिर से जारी किया गया। यह संशोधन विकासमान आईआरडी बाजार परितंत्र और वित्तीय प्रणाली की जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है, तथा इसका उद्देश्य रुपया आईआरडी बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना है।

V.8 म्युनिसिपल बॉण्ड के बाजार को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार के परामर्श से ऐसे बॉण्ड को रेपो लेनदेन के लिए पात्र संपार्श्विक के तौर पर अधिसूचित किया गया।

V.9 कर्ज प्रतिभूतियों में विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के निवेश को नियंत्रित करने वाली निवेश प्रणाली को पुनर्निर्धारित किया गया। कॉरपोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश के लिए सामान्य मार्ग के तहत समष्टि-विवेकपूर्ण नियंत्रणों की समीक्षा की गई, और लघु-अवधि निवेश सीमा और संकेंद्रण सीमा वापस ले ली गई। विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों में अधिशेष जमा को केंद्रीय सरकार प्रतिभूति (खजाना बिल सहित), अपरिवर्तनीय डिबेंचर/ बॉण्ड और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत निवेश सीमाओं की उपलब्धता के संबंध में पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने और कारोबार सुगमता को और बढ़ाने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल 2026 से वीआरआर के तहत

निवेश को सामान्य मार्ग के तहत एफपीआई निवेश की सीमा में गिना जाएगा; और जिन एफपीआई ने न्यूनतम प्रतिधारण अवधि से अधिक लंबे समय तक प्रतिधारण अवधि का फायदा उठाया है, उनके पास न्यूनतम प्रतिधारण अवधि खत्म होने के बाद अपने पोर्टफोलियो को पूर्णतः या अंशतः परिसमापन करने और वीआरआर से बाहर निकलने का विकल्प होगा।

V.10 तटीय और अपतटीय वित्तीय बाजारों के बढ़ते समेकन, प्रौद्योगिकीय विकास और बढ़ती उत्पाद विविधता को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म से संबंधित विनियामकीय फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई। 36 महीने (13 महीने से) तक के विदेशी मुद्रा वायदा संविदा (विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट) के लिए व्यापार और गारंटीकृत निपटान सुविधाएं शुरू की गईं। संशोधित मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट दर-आधारित स्वैप और विदेशी मुद्रा ऑप्शन, ऐसे लिखतों के व्यापार और निपटान प्रक्रिया के इलेक्ट्रॉनिकीकरण को संभव बनाएंगे। सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासी व्यापार को इलेक्ट्रॉनिक बनाने के उद्देश्य से, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अनाम ऑर्डर मिलान प्लेटफॉर्म – तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) को वैश्विक बॉण्ड व्यापार प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रावधान किया गया। टोकनीकरण और विभाजित लेजर तकनीकी (डीएलटी) जैसी नई प्रौद्योगिकी का लाभ लेने के लिए, होलसेल केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) का इस्तेमाल करके निपटान के साथ-साथ एकीकृत बाजार इंटरफेस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर टोकनीकृत रूप में जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) को जारी करने और व्यापार करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है।

V.11 रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों में व्यापार और निपटान अवधि की समीक्षा हेतु कार्यदल (अध्यक्ष: श्री राधा श्याम रथ, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक)

की संस्तुतियों के आधार पर, मुद्रा बाजार के संपार्श्विकृत और असंपार्श्विकृत दोनों हिस्सों की अवधि बढ़ा दी गई।

V.12 फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) को वित्तीय बाजारों में स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के तौर पर मान्यता मिल गई है।

V.13 मुद्रा बाजार की सूक्ष्म-संरचना के उद्भव के साथ-साथ संपार्श्विक बाजार की प्रमुखता को देखते हुए, जमानती मुद्रा बाजारों [बास्केट रेपो और ट्राइपार्टी रेपो (टीआरईपी)] पर आधारित एक बेंचमार्क - को मंजूरी दी गई। फाइनेंसियल बेंचमार्क्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने 7 जुलाई 2025 से एसओआरआर बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया।

V.14 तटीय विदेशी मुद्रा बाजार को गहन बनाने और बृहत मुद्रा जोड़ियों (पेयर्स) में सीधे दर कोट करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने हेतु, एफबीआईएल को, भारत के प्रमुख व्यापार-सहयोगियों की मुद्राओं में संदर्भ दरों को प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया। एफबीआईएल ने 5 जनवरी 2026 से अतिरिक्त संदर्भ दरों का प्रकाशन शुरू किया।

V.15 बाजार की स्थिति सुव्यवस्थित रखने और बहुत अधिक उतार-चढ़ाव और सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए, प्राधिकृत व्यापारियों को अधिदेशित किया गया था कि वे प्रत्येक कारोबारी दिन के आखिर में तटीय प्रदेय (ऑनशोर डेलिवरेबल) बाजार में भारतीय रुपया में अपनी निवल ओपन पोजीशन (एनओपी-आईएनआर) यूएस\$ 100 मिलियन से कम रखें, और यह काम जल्द से जल्द 10 अप्रैल 2026 तक करना होगा।

2026-27 के लिए एजेंडा

V.16 2026-27 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- विदेशी मुद्रा रोकड़/ टॉम/ स्पॉट व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तन और लेनदेन प्रभार का खुलासा अधिदेशित कर रिटेल उपयोगकर्ता के लिए कीमत निर्धारण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना; और
- सरकारी प्रतिभूति में द्वितीयक बाजार लेनदेन से जुड़े सभी परिपत्र को मास्टर निदेश में एक साथ समेकित करना।

3. वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.17 एफएमओडी का मुख्य उत्तरदायित्व, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के लक्ष्यों के कार्यान्वयन की दिशा में चलनिधि प्रबंधन¹ परिचालनों का संचालन करना और तटीय और अपतटीय बाजार परिचालनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में सुव्यवस्था सुनिश्चित करना है।

2025-26 के लिए एजेंडा

V.18 उक्त वर्ष के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा (पैराग्राफ V.19)
- यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन का संचालन (पैराग्राफ V.20); और
- बाजार परिचालन रणनीतियों का निरंतर मार्गदर्शन करने के लिए वित्तीय बाजारों से संबंधित नीति-उन्मुख अनुसंधान और विश्लेषण करना (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ V.21]।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.19 फरवरी 2020 से चल रहे चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्यदल (आईडब्ल्यूजी)

¹ चलनिधि प्रबंधन परिचालनों से संबंधित ब्योरा इस रिपोर्ट के अध्याय III में है।

बनाया गया था। आंतरिक कार्यदल की संस्तुतियों और अलग-अलग हितधारकों से मिले फीडबैक के आधार पर, 30 सितंबर 2025 से संशोधित चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क लागू किया गया।

V.20 भू-राजनीतिक तनाव और टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं में वृद्धि के बीच भारतीय रुपया (आईएनआर) में उतार-चढ़ाव देखे गए। अंतिम तिमाही में वस्तु व्यापार घाटा बढ़ने और ईंधन-तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने मुश्किलें और बढ़ा दीं। रिजर्व बैंक ने, बाजार को सुव्यवस्थित रखने और विनिमय दर में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए, तटीय/अपतटीय ओटीसी और एक्सचेंज में खरीदे बेचे गए मुद्रा व्युत्पन्नी सेगमेंट में परिचालन के जरिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किए।

V.21 विभाग ने, 2025-26 के दौरान वित्तीय बाजारों से जुड़ी नीति पर आधारित अनुसंधान और विश्लेषण जारी रखा। इन अध्ययनों में, जमा प्रमाणपत्र जारी करने के चालक, आईएनआर के उचित मूल्य का आकलन करने के लिए वैकल्पिक सूचकांक (नॉमिनल प्रभावी विनिमय दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के अलावा), वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय सरकारी बॉण्ड को शामिल करने के प्रभाव, विकसित हो रही मुद्रा बाजार गतिशीलता और भारत में नीति संचरण की क्षमता, शामिल हैं।

2026-27 के लिए एजेंडा

V.22 2026-27 के दौरान, विभाग की योजना निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने की है:

- मौद्रिक नीति संचरण के उद्देश्य से चलनिधि प्रबंधन परिचालनों का प्रभावी संचालन;
- यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन करना; और

- बाजार परिचालन रणनीतियों के सतत मार्गदर्शन के लिए वित्तीय बाजारों से संबंधित नीतिगत अनुसंधान और विश्लेषण।

4. विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.23 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रस्तावना की शर्तों के अनुसार, विदेशी मुद्रा विभाग का अधिदेश, बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना है।

2025-26 के लिए एजेंडा

V.24 विभाग ने 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली का युक्तिकरण (पैराग्राफ V.25)
- उदारकृत धन-विप्रेषण योजना (एलआरएस) का युक्तिकरण (पैराग्राफ V.26)
- भारतीय रुपया में उधार लेने और उधार देने के लेनदेन पर निदेशों की समीक्षा करना ताकि इन निदेशों को तर्कसंगत बनाकर 'मास्टर निदेश- बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), व्यापार ऋण और संरचित दायित्व' में विलय किया जा सके (पैराग्राफ V.27);
- फेमा, 1999 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए प्राधिकरण ढांचे (ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क) की समीक्षा (पैराग्राफ V.28);
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (एफईएम) (गैर-कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 का युक्तिकरण (पैराग्राफ V.29)
- बीमा विनियमावली, 2015 की समीक्षा (पैराग्राफ V.30)
- जमा विनियमावली, 2016 का समीक्षा (पैराग्राफ V.31); और

- एफईएम [भारत में एक शाखा कार्यालय (बीओ) या एक संपर्क कार्यालय (एलओ) या एक परियोजना कार्यालय (पीओ) या किसी अन्य कारोबारी स्थान की स्थापना] विनियमावली, 2016 की समीक्षा (पैराग्राफ V.32)।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.25 एफईएम (गारंटी) विनियमावली, 2026 को 10 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था। समीक्षित ढांचे में स्वचालित मार्ग के तहत सक्षम गारंटी के दायरे का विस्तार किया गया है, जबकि पिछले ढांचे में अनिवासी संस्थाओं द्वारा जारी गारंटी के लिए कोई सक्षमकारक प्रावधान नहीं थे। समीक्षा के बाद, प्रधान देनदार और जमानतदार के बीच गारंटी लेनदेन के लिए प्राथमिक शर्तें ये हैं कि अंतर्निहित लेनदेन फेमा, 1999 के तहत निषिद्ध नहीं हो, तथा जमानतदार और देनदार, जहां भी उनका निवासी कानून अलग-अलग है, मौजूदा उधार लेने / उधार देने के ढांचे के तहत पात्र ऋणदाता और उधारकर्ता हैं। इसके अलावा, सभी गारंटियों - जारी, संशोधित और लागू - के लिए त्रैमासिक आधार पर एक व्यापक रिपोर्टिंग शुरू की गई है।

V.26 एलआरएस समीक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं: चालू खाता विप्रेषण के लिए अनुपालन बोझ कम करने हेतु दिशानिर्देशों का युक्तिकरण, मौजूदा एलआरएस को कवर करने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अनुमत उद्देश्य, भुगतान प्रविधि/मुद्रा और घोषणा भी शामिल हैं। यह समीक्षा प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।

V.27 भारतीय रुपया (आईएनआर) में उधार लेने और देने के लेनदेन संबंधी निदेशों को 'मास्टर निदेश - बाह्य

वाणिज्यिक उधार, व्यापार क्रेडिट और संरचित देनदारी के बजाय एक ही दस्तावेज 'विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना और देना) विनियमावली, 2018 (फेमा 3आर)' में समेकित करने का निर्णय लिया गया है। निवासी भारतीय व्यक्ति (पीआरआई) द्वारा अनिवासी भारतीय व्यक्ति (पीआरओआई) से आईएनआर में उधार लेने से संबंधित तर्कसंगत प्रावधानों को, 16 फरवरी 2026 को अधिसूचित, 'फेमा 3आर' में एक संशोधन² के जरिए समेकित किया गया है। आईएनआर में उधार देने संबंधी प्रावधानों के संशोधित विनियमों की अभी समीक्षा की जा रही है।

V.28 विनियामकीय त्रुटियों को दूर कर और कारोबारी सुगमता बढ़ाकर, समुचित सुरक्षा-प्रणाली के रखरखाव के साथ-साथ विदेशी मुद्रा सेवाओं की उपलब्धता और परिचालनगत क्षमता को बेहतर बनाने के लिए प्रमाणीकरण फ्रेमवर्क को युक्तिसंगत और सरल बनाया जा रहा है।³

V.29 विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखत) नियम, 2019 की समीक्षा की गई है, जिसमें प्रक्रिया को अधिक सिद्धांत-आधारित बनाने, निवेश प्राप्त करने वाली इकाइयों पर एक समान नियम लागू होना सुनिश्चित करने, वर्तमान घरेलू कानूनों के साथ ओवरलैप से बचने और विदेशी निवेश नियमों को एफडीआई नीति से स्पष्टतः अलग करने, पर ध्यान दिया गया है। संशोधित नियम नवंबर 2025 में भारत सरकार को विचार के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।

V.30 संबंधित हितधारकों से मिली टिप्पणियों के आधार पर, वर्तमान फेमा बीमा विनियमावली, 2015⁴ अभी आंतरिक समीक्षा के अधीन हैं।

² विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना और उधार देना) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2026

³ एफईएम (अधिकृत व्यक्ति) विनियमावली, 2026 को 06 मई 2026 को अधिसूचित किया गया है, ताकि उचित जाँच और संतुलन बनाए रखते हुए अधिकृत व्यक्तियों के लिए, प्राधिकार देने और नवीनीकरण के ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जा सके। इसके कुछ प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं: संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) के लिए नए प्राधिकार देना बंद करना (जबकि मौजूदा एफएफएमसी को बनाए रखना), स्थायी प्राधिकार देना, एफएफएमसी और गैर-बैंकिंग प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-II के लिए न्यूनतम वार्षिक विदेशी मुद्रा कारोबार की शर्त, प्राधिकृत व्यापारी के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए विदेशी मुद्रा संपर्क (फॉरेक्स कॉरस्पॉन्डेंट) की शुरुआत, एडी श्रेणी-II के लिए गतिविधियों के दायरे का विस्तार, और अपील तंत्र।

⁴ रिजर्व बैंक अधिसूचना संख्या फेमा 12(आर)/2015-आरबी, दिनांक 29 दिसंबर 2015

V.31 वर्तमान जमा विनियमावली की आंतरिक समीक्षा के अनुसरण में, जमाराशियों को शासित करने वाली फेमा विनियमावली⁵ और निवासी भारतियों के विदेशी मुद्रा खातों को शासित करने वाली फेमा विनियमावली⁶ की एक साथ समीक्षा की जा रही है। इसलिए, संशोधित विनियमावली-समूह अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

V.32 भारत में एलओ/बीओ/पीओ/कारोबार का अन्य स्थान स्थापित करने के लिए वर्तमान फ्रेमवर्क की पूरी तरह से समीक्षा की गई है। संशोधित विनियम सिद्धांत-आधारित हैं और एडी बैंकों को अधिक शक्ति देने और अनुपालन-बोझ कम

करने में मदद करते हैं, जिससे कारोबार सुगम हो जाता है। संशोधित विनियमों का मसौदा अक्टूबर 2025 में रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक फीडबैक लेने के लिए प्रकाशित किया गया था। उस पर फीडबैक प्राप्त होने के बाद, संशोधित मसौदा विनियमों को भारत सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा है।

प्रमुख पहलें

V.33 पिछले कुछ वर्षों में, रिजर्व बैंक ने चालू और चुनिंदा पूंजी खाता लेनदेन, दोनों के लिए, आईएनआर के बढ़ते उपयोग के माध्यम से, एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में इसकी भूमिका को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं (बॉक्स V.1)।

बॉक्स V.1: सीमा-पार व्यापार के लिए भारतीय रुपया और स्थानीय मुद्राओं का उपयोग

इनवॉइसिंग और निपटान मुद्रा के रूप में भारतीय रुपया की वृद्धि से, विनिमय दर जोखिम से सुरक्षा मिलने की संभावना है, परिवर्तनीय मुद्राओं में महंगी विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि को बनाए रखने की आवश्यकता कम हो सकती है, द्विपक्षीय विनिमय दर बाजार सहजता से विकसित तो सकते हैं और विदेशी मुद्रा लेनदेन में लेनदेन लागत को नियंत्रित किया जा सकता है। चालू/पूजी खाता लेनदेन के लिए विनिमय के सीमा-पार माध्यम के रूप में भारतीय रुपया की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रमुख नीतिगत पहलों में शामिल हैं:

- 1) भारत में प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-1 बैंकों में भारत के भागीदार देशों में संपर्क बैंकों द्वारा खोले जाने वाले विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों (एसआरवीए) का प्रावधान;
- 2) साझेदार देशों के साथ स्थानीय मुद्रा व्यवस्था (एलसीए) (जिसमें भारतीय रुपया या व्यापार भागीदार की स्थानीय मुद्रा में सीमा-पार व्यापार का इनवॉइसिंग / निपटान शामिल है);
- 3) पीआरओआई को पीआरआई के साथ सभी अनुमेय चालू और पूंजी खाता लेनदेन और अन्य पीआरओआई के साथ सभी वास्तविक (बोना फाइड) लेनदेन के लिए भारत के बाहर एडी बैंकों की शाखाओं में आईएनआर-मूल्यवर्ग के खाते खोलने और रखने में सक्षम बनाना।

4) प्रत्यावर्तनीय रुपया खातों के बीच सभी वास्तविक लेनदेन के लिए निधियों के अंतरण की अनुमति।

5) भारत में अनुमत विदेशी निवेश के लिए भुगतान एसआरवीए जमाशेष से सक्षम किया गया है।

मई 2026 तक, एलसीए की व्यवस्था चार क्षेत्राधिकारों (संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, मालदीव और मॉरीशस) के साथ की गई है और एसआरवीए को 35 भागीदार देशों (एफडीडीआई एसआरवीए निर्देशिका के अनुसार) में संपर्क बैंकों द्वारा खोला गया है।

जुलाई 2022 से भारतीय रुपया आधारित इनवॉइसिंग और निपटान में काफी तेजी आई है। अगस्त 2022-जुलाई 2025 की अवधि के दौरान, भारतीय रुपया में इनवॉइसिंग किए गए आयात और निर्यात की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) क्रमशः 20.9 प्रतिशत और 12.7 प्रतिशत रही है। इसके अलावा, भारतीय रुपया (2025-26) में व्यापार इनवॉइसिंग और निपटान पर नवीनतम डेटा पिछले वर्ष की इसी अवधि (सारणी 1 और 2) की तुलना में निर्यात इनवॉइसिंग (6.5 प्रतिशत), आयात इनवॉइसिंग (9.5 प्रतिशत), निर्यात निपटान (2.7 प्रतिशत) और आयात निपटान (41.2 प्रतिशत) के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रदर्शित करता है।

(जारी)

⁵ रिजर्व बैंक अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)/2016-आरबी, दिनांक 1 अप्रैल 2016

⁶ रिजर्व बैंक अधिसूचना संख्या फेमा 10(आर)/2015-आरबी, दिनांक 21 जनवरी 2016

सारणी 1 : भारत के व्यापार के लिए भारतीय रुपया इनवॉइसिंग

(₹ करोड़)

अवधि (अप्रैल-मार्च)	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4
आयात	1,94,162 (3.7)	2,59,940 (4.5)	2,84,688 (4.7)
निर्यात	2,86,794 (5.9)	3,07,281 (5.9)	3,27,370 (6.2)

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े भारतीय रुपया के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।
2. निर्यात में वस्तु और सॉफ्टवेयर शामिल हैं जबकि आयात में केवल वस्तु शामिल हैं।
3. सभी आंकड़े ईडीपीएमएस/आईडीपीएमएस पोर्टल पर एडी बैंक रिपोर्टिंग पर आधारित हैं और इसलिए समय-समय पर अपडेट/सुधार के अधीन हैं।

स्रोत: ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस

भारतीय रुपया अंतरराष्ट्रीयकरण प्रक्रिया सभी व्यापारिक भागीदारों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद रही है, और पारस्परिकता के सिद्धांतों के आधार पर, इसने कई अन्य उभरते बाजार की मुद्राओं में व्यापार इनवॉइसिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस संबंध में कई अतिरिक्त उपाय किए गए हैं, जैसे: (i) पात्र कॉरपोरेट ऋण में,

सारणी 2: भारतीय व्यापार का भारतीय रुपया में निपटान

(₹ करोड़)

अवधि (अप्रैल-मार्च)	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4
आयात	99,680 (1.8)	1,13,088 (1.9)	1,59,691 (2.5)
निर्यात	1,75,086 (3.6)	1,67,448 (3.2)	1,71,916 (3.0)

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े भारतीय रुपया के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।
2. निर्यात में वस्तु और सॉफ्टवेयर शामिल हैं जबकि आयात में केवल वस्तु शामिल हैं।
3. सभी आंकड़े ईडीपीएमएस/आईडीपीएमएस पोर्टल पर एडी बैंक रिपोर्टिंग पर आधारित हैं और इसलिए समय-समय पर अपडेट/सुधार के अधीन हैं।

स्रोत: ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस

एसआरवीए में अधिशेष जमाराशि रखना संभव बनाना, और (ii) एडी बैंकों को, व्यापार लेनदेन के लिए, अनिवासियों (नेपाल/ भूटान/ श्रीलंका के निवासी सहित इन अधिकार क्षेत्रों में स्थित बैंक) को, भारतीय रुपया में ऋण देने की अनुमति देना।

स्रोत: आरबीआई।

V.34 सभी ज़रूरी विदेशी निवेश डेटा को, विदेशी निवेश रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (एफआईआरएमएस) प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाने के लिए एक व्यापक डिजिटाइज़ेशन पहल शुरू की गई है। आखिरकार, इससे अधिकृत हितधारक और एडी बैंक, एफआईआरएमएस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक विदेशी निवेश पावती जनरेट कर पाएंगे।

V.35 अप्रैल 2025 से, निर्यातकों को भारत मार्ट (यूईई में एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क-आधारित मार्केटप्लेस) को निर्यात की गई वस्तु की पूरी निर्यात आय को, वेयरहाउस से वस्तु की बिक्री की तिथि से नौ महीने के भीतर, प्राप्त और प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, युक्ति संगत होने पर और बिना किसी पूर्व शर्त के, वे वेयरहाउस खोल/ किराए पर ले सकते हैं और अपना कार्यालय स्थापित करने और कारोबार परिचालन जारी रखने के लिए आरंभिक और नियमित व्यय हेतु निधि विप्रेषित कर सकते हैं।

V.36 भारत में मार्च 2024 से निवेश साधनों द्वारा पीआरओआई को आंशिक रूप से भुगतान की गई इकाइयाँ (पीपीयू) जारी करने को, उनके प्रभावी होने से पहले, वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) द्वारा रिपोर्टिंग सहित आवश्यक

प्रशासनिक कार्रवाई पूरा करने की शर्त पर, कंपाउंडिंग के माध्यम से नियमित करने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार, मई 2025 में यह स्पष्ट किया गया था कि निवेश साधन उक्त स्पष्टीकरण की तिथि से 180 दिनों के भीतर पीपीयू के पूर्व-परिपत्र निर्गम की रिपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि, रिपोर्टिंग ढांचे के विनियमों के अनुसार, निवेश साधनों द्वारा पीपीयू के परिपत्रोत्तर निर्गम के लिए 30-दिवसीय रिपोर्टिंग समय-सीमा चालू है।

V.37 जून 2025 से प्रभावी, आयातकों को कुछ शर्तों के अधीन, यूएस \$50 मिलियन तक के शिपिंग जहाजों के आयात के लिए बैंक गारंटी के बिना या शर्त रहित अप्रतिसंहरणीय वैकल्पिक साख पत्र के बिना अग्रिम विप्रेषण की अनुमति दी गई है।

V.38 जून 2025 में, एफईएम (गैर-कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 में संशोधन द्वारा, उन क्षेत्रों या गतिविधियों में शामिल भारतीय कंपनियों को जहां एफडीआई निषिद्ध है, पीआरओआई के रूप में वर्गीकृत पूर्व-मौजूदा शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई थी कि निर्गम के उपरांत निवेश प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनियों

के शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा, इस प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि से पहले ऐसे शेयरधारकों को जारी किए गए किसी भी बोनस शेयर को फेमा के तहत लागू प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया माना जाएगा।

V.39 इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाकर एसआरवीए खोलने को प्रोत्साहित करने के लिए, एडी बैंकों को अगस्त 2025 में, रिज़र्व बैंक से मंजूरी लिए बिना, विदेशी संपर्क बैंकों का एसआरवीए खोलने की अनुमति दी गई है।

V.40 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में रहने वाले व्यक्ति के विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015⁷ में संशोधन करके, भारतीय निर्यातकों को, भारत के बाहर के बैंकों में खोले गए विदेशी मुद्रा खाता में पैसे मिलने की तिथि से, वायदा वचनों (फॉरवर्ड कमिटमेंट्स) को समायोजित करने के बाद, उपयोग नहीं की गई निधि को निम्नलिखित अवधि के अंदर प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है: (क) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) वाले बैंकों में खाता होने पर तीन महीने के अंदर; या (ख) बाकी सभी क्षेत्राधिकारों के लिए अगले महीने।

V.41 आईएनआर में सीमा-पार व्यापार लेनदेन को बढ़ावा देने और ऐसे लेनदेन करने हेतु पीआरओआई को आईएनआर चलनिधि/ संसाधन प्रदान करने के लिए, एडी बैंकों को अक्टूबर 2025 से भूटान, नेपाल या श्रीलंका में रहने वाले व्यक्तियों को आईएनआर में ऋण देने की अनुमति दी गई है, जिसमें इन क्षेत्राधिकारों के बैंक भी शामिल हैं। इससे, स्थानीय मुद्रा में अंतर-केंद्रीय बैंक स्वैप, अंतर-सरकारी ऋण व्यवस्था अथवा भारत में एडी बैंकों द्वारा ऋण व्यवस्था के लिए विशेष अनुमति, पर निर्भरता और/या अपेक्षा में कमी आने की उम्मीद है।

V.42 मर्चेन्टिंग व्यापारियों को, उनके व्यापारिक लेनदेन को सुप्रबंधित करने में मदद करने हेतु, अक्टूबर 2025 में यह निर्णय लिया गया कि मर्चेन्टिंग व्यापार लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा परिव्यय की समयावधि चार महीने से बढ़ाकर छः महीने कर दी जाए।

V.43 ईडीपीएमएस⁸ और आईडीपीएमएस⁹ में प्रविष्टियों को समय पर बंद करने की सुविधा प्रदान करने और निर्यातकों/ आयातकों पर अनुपालन बोझ कम करने के लिए, एडी बैंकों को, संबंधित निर्यातक द्वारा प्रदान की गई घोषणा के आधार पर – ‘कि राशि प्राप्त हो गई है’ या संबंधित आयातक द्वारा – ‘कि राशि का भुगतान कर दिया गया है’, अक्टूबर 2025 में ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस में ₹10 लाख प्रति प्रविष्टि/ बिल तक के मूल्य के बराबर प्रविष्टियों (लंबित प्रविष्टियों सहित) का समाधान करने और बंद करने तथा घोषणा के आधार पर घोषित मूल्य या इनवॉइसिंग मूल्य में किसी भी घटत को स्वीकार करने, को सूचित किया गया था। एडी बैंकों को यह भी सूचना दी गई थी कि वे छोटे मूल्य के निर्यात और आयात लेनदेन के रखरखाव के लिए लगाए गए शुल्कों की समीक्षा करें (यह सुनिश्चित करते हुए कि वे प्रदान की गई सेवाओं के अनुरूप हैं) और किसी भी विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुपालन में देरी के लिए कोई जुर्माना न लगाएं।

V.44 नवंबर 2025 में, भारत से निर्यात की गई वस्तु/ सॉफ्टवेयर/ सेवा का पूरा निर्यात मूल्य वसूली और प्रत्यावर्तन की समयावधि, भारत से निर्यात की तिथि से, नौ महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दी गई, ताकि निर्यातक कारोबार को प्रभावित करने वाले वैश्विक संकटों से बेहतर तरीके से निपट सकें। इसके अलावा, विदेशी व्यापार महानिदेशालय के कुछ हालिया नीतिगत बदलावों के अनुसार, वस्तु के शिपमेंट की समयावधि अग्रिम भुगतान (निर्यात के लिए) मिलने की तिथि से, एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष या करार के अनुसार, जो भी बाद में हो, कर दी गई है।

⁷ रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या फेमा 10(आर)/2015-आरबी, दिनांक 21 जनवरी 2016

⁸ निर्यात डेटा प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली।

⁹ आयात डेटा प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली।

V.45 दोनों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, मौजूदा मुद्रा निर्यात/आयात फ्रेमवर्क की समीक्षा के बाद, दिसंबर 2025 में यह निर्णय लिया गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक नहीं है, उसे निम्नलिखित की अनुमति दी जाए: भारत से नेपाल या भूटान ले जाने या भेजने के लिए, और नेपाल या भूटान से भारत लाने के लिए, भारत सरकार के मुद्रा नोट और आरबीआई नोट, किसी भी राशि में, ₹100 तक के मूल्यवर्ग में; भारत से नेपाल या भूटान ले जाने के लिए, और नेपाल या भूटान से भारत लाने के लिए, ₹100 से ज्यादा के मूल्यवर्ग वाले नोट, जिनकी कुल सीमा ₹25,000 तक हो।

V.46 विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात), विनियमावली, 2026, जनवरी 2026 में राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। ये विनियम मुख्य रूप से सिद्धांत-आधारित हैं, इनमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार के लिए अभिशासकीय प्रावधान हैं, और इनका उद्देश्य, खासकर छोटे निर्यातकों और आयातकों के लिए, कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना है। उक्त विनियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे।

V.47 फरवरी 2026 में, संशोधन द्वारा, ईसीबी फ्रेमवर्क को पूरी तरह से युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: क) ऋण प्रवाह के अवसरों को बढ़ाने के लिए पात्र उधारकर्ता और मान्यता प्राप्त उधारदाता के आधार का विस्तार; ख) उधार लेने की सीमा को उधारकर्ता की वित्तीय हैसियत से जोड़ना; ग) अंतिम-उपयोग प्रतिबंधों और न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि की अपेक्षाओं में उदार बनाना; घ) बाजार-निर्धारित ब्याज दर पर ईसीबी का लाभ लेने में मदद करना; और ङ) अनुपालनगत बाध्यताएँ कम करने हेतु रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को सहज बनाना।

2026-27 के लिए एजेंडा

V.48 2026-27 के दौरान, विभाग की योजना निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने की है:

- विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 का युक्तिकरण: एक व्यापक समीक्षा;
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा धारित विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 की समीक्षा;
- जमा विनियमावली, 2016 की समीक्षा;
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) विनियमावली, 2015 की समीक्षा।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-कर्ज लिखत) नियम, 2019 का युक्तिकरण;
- एफईएम [भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) या संपर्क कार्यालय (एलओ) या परियोजना कार्यालय (पीओ) या कारोबार के किसी अन्य स्थान की स्थापना] विनियमावली, 2016 की समीक्षा; और
- विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024 की समीक्षा।

5. निष्कर्ष

V.49 वर्ष 2025--26 के दौरान, रिजर्व बैंक ने कारोबार सुगमता बढ़ाने हेतु बाह्य क्षेत्र के विनियमों को युक्तिसंगत बनाने और भारतीय रुपया में सीमा-पार लेनदेन को प्रोत्साहित करने के अलावा अन्य कई प्रयासों के माध्यम से वित्तीय बाजारों को और विकसित और गहन बनाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। भविष्य में, चलनिधि का परिचालन मौद्रिक नीति के रुख के तालमेल में जारी रहेगा, जबकि विदेशी मुद्रा संचालन सिद्धांत-आधारित होगा जिसका उद्देश्य भारतीय रुपया की विनिमय दर में व्यवस्थित उतार-चढ़ाव सुनिश्चित करना होगा।